भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 156
गुरुवार, 2 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

आरसीएस-उड़ान की उपलब्धियां

156. श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना को शुरू हुए पांच वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं और यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करते समय सरकार के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां है

(ख) क्या सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए उड़ान योजना शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है,

(ग) तमिलनाडु राज्य में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है,

(घ) विमानन क्षेत्र के समग्र विकास में उड़ान योजना का कितना योगदान है;

(ङ) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान उड़ान योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/ प्रस्तावित हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (च): नागर विमानन मंत्रालय ने देश के अपरिचालित और अल्प-परिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के उद्देश्य से, दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की है। उड़ान एक बाजार आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें, विशिष्ट मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर, उड़ान योजना के तहत बोली लगाने के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।

योजना के तहत, दिनांक 30.01.2023 तक देश भर में नौ हेलीपोर्ट्स और दो वाटर एयरोड्रोम्स सहित 72 हवाईअड्डों को शामिल करते हुए 459 उड़ान मार्गों पर प्रचालन आरंभ कर दिया गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत, अब तक 1.13 करोड़ से अधिक यात्रियों ने 2.16 लाख से अधिक उड़ानों में यात्रा की है। नागर विमानन क्षेत्र और आर्थिक विकास के बीच का संबंध सर्वविदित है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि अच्छे हवाई संपर्क से आर्थिक वृद्धि 3.1 गुणा होगी और रोजगार के अवसरों

में 6.1 गुणा की वृद्धि होगी। योजना को लागू करते समय निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

i) कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रतिकूल प्रभाव
ii) सिविल हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों की तैयारी न होना, जो भूमि की उपलब्धता, क्षेत्रीय अवसंरचना के निर्माण आदि से संबंधित हो सकता है।
iii) अवार्ड किए गए मार्गों पर प्रचालन की अस्थिरता।
iv) चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) की तैयारी न होना
v) मुंबई और पुणे जैसे मेट्रो हवाईअड्डों पर स्लॉट की अनुपलब्धता।

उड़ान योजना के तहत उड़ानों के प्रचालन हेतु तमिलनाडु में सलेम, नेवेली, तंजौर, वेल्लोर और रामनाद हवाईअड्डों को अवार्ड किया गया है। सलेम हवाईअड्डे से, उडान योजना के तहत उड़ानों का प्रचालन आरंभ हो चुका है।

सरकार ने उड़ान योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 2024 तक एक सौ हवाईअड्डों को विकसित करने और योजना की अवधि के दौरान 1000 उड़ान मार्गों पर प्रचालन आरंभ करने की योजना बनाई है। उड़ान एक सतत योजना है जहां योजना के तहत अधिक गंतव्यों/स्टेशनों को शामिल करने के लिए समय-समय पर, बोलियों के दौर आयोजित किए जाते हैं।

****